LOK SABHA

Friday, September 24, 1965/Asvina 2, 1887 (Saka)

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of Cement

+

*814. **Shri Bagri:**
Shri Hem Raj:
Dr. P. Srinivasan:
Shri Paramasivan:
Shri Jashvant Mehta:
Dr. Mahadeva Prasad:
Shri Kajrolkar:
Shri Mohammed Koya:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Basappa:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of cement in the country;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to improve the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4980/65].

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय : इस बयान के मुताबिक सीमेंट की 16 से 20 सैंकड़ा तक कमी है, परन्तु हम व्यवहार में देखते हैं कि गांवों में रहने वाले लोगों को सीमेंट का

5 सैंकड़ा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग ग्रामों में रहते हैं और जो बहुत छोटे छोटे मकान बनाते हैं उनको कितने सैंकड़ा सीमेंट मिलता है और बड़ बड़े कामों में कितने सैंकड़ा सीमेंट इस्ते-माल होता है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) इस अनुपात का अन्दाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितने परसेंट सीमेंट गांवों में मिलता है और कितने परसेंट शहरी जगहों में मिलता है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सिर्फ परसेंटेज के बारे में नहीं है । आज ग्रामों में सीमेंट मिलता ही नहीं है— नहीं के बराबर मिलता है, जबकि सीमेंट की कमी 15, 16 परसेंट है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब कहते हैं कि परसेंटेज बताना मुश्किल है ।

श्री बागड़ी : मैं यह जानना चाहता हूं कि नागरिकों को जो सीमेंट नहीं मिल रहा है उसके लिए सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है । क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक किन कारणों से सीमेंट नहीं मिल रहा था और लोगों को आइन्दा ठीक तरह से सीमेंट देने के बारे में वह क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सीमेंट का उत्पादन हर साल एक से डढ़ मिलियन टन के रेट से बढ़ता जा रहा है । मेरा ख्याल है कि दो तीन साल में हमारे गांवों में भी और दूसरे लोगों को भी सीमेंट काफी मिक़दार में मिल जायेगा । हमें गांवों का ख़ास तौर से ख्याल है ।

हम स्टेट्स को कहा करते हैं, कि जहां तक हो सके गांवों को, और खास तौर से एग्रीकल्चरल कामों को तरजीह दी जाये ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है । मैंने पूछा है कि किन कारणों की बिना पर गांवों में अब तक सीमेंट नहीं मिला है, और आगे कौन से तरीके अपनाये जायेंगे, जिस से गांवों में सीमेंट मिले । गांवों को हर एक चीज से—चीनी से भी और सीमेंट से भी—वंचित किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस वक्त सीमेंट थोड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि दो तीन साल में हम इतना सीमेंट पैदा कर लेंगे कि गांवों और दूसरी जगहों की जरूरत पूरी हो जायेगी ।

श्री बागड़ी : इस वक्त 15, 16 सैकड़े की कमी है । गांवों को उसके मुताबिक तो सीमेंट दिया जाना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : इस वक्तव्य में सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिये पैदावार बढ़ाने की बात कही गई है । सरकार की ओर से सीमेंट उद्योग को कहा जाता है कि वह करीब करीब 33 फी सदी पुराने बोरों का इस्तेमाल करे । लेकिन उन बोरों, जूट बग्स, का दोबारा इस्तेमाल करने से काफी सीमेंट का नुकसान होता है । क्या सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बात पर भी विचार किया है कि पुराने बोरों को दोबारा इस्तेमाल करने की जो नीति है, उसको बदला जाये और यह प्रतिशत घटा दिया जाये ?

श्री त्रि. ना. सिंह : मेरी समझ में इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है—इस लिए कि आज-कल की स्थिति में हमारे पास बोरों के जो कुछ भी रिसोर्सिज हैं, उनका मैक्सिमम यूज करना चाहिए ।

श्री मधु लिमये : उस से सीमेंट का जो नुकसान होता है, उसका क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर बोरे नहीं रहेंगे, तो सीमेंट किस में जायेगा ?

श्री मधु लिमये : पुराने बोरों का इस्तेमाल करने से सीमेंट का नुकसान होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर थोड़े से सीमेंट को बचायेंगे, तो बोरों का नुकसान होगा ।

श्री रामसेवक यादव: क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि एक ओर तो खेती के कामों के लिए सीमेंट नहीं मिलता है, जैसे कुओं आदि के लिए, और दूसरी ओर बड़ी बड़ी कोठियों के लिये काले बाजार से ज्यादा भाव पर सीमेंट मिल जाता है । यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या आदेश दिये जा रहे है ?

श्री त्रि. ना. सिंह : काले बाजार की जानकारी शायद माननीय सदस्य को ज्यादा होगी—मुझ नहीं है । लेकिन जहां कहीं भी इस बारे में शिकायत आती है, हम उस की तरफ ध्यान देते हैं और कारवाई करते है ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय : आधे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री रामसेवक यादव : क्या मंत्री महोदय को काले बाजार की जानकारी नहीं है ?

Shri Basappa: Are Government aware of the availability of the raw materials in the Vasadurga area of Chitaldrug district of Mysore State? Is it a fact that the Chief Minister of Mysore has made a reference to this? If so, what action has been taken by Government?

Mr. Speaker: Each State cannot be taken up now.

Shri Basappa: More production of cement is also covered in the question.

Mr. Speaker: We might put a general question.

Shri Basappa: Please let him answer the question.

Shri T. N. Singh: Whenever the Chief Minister of Mysore as also of

other States have written, I have tried to accommodate them to the best of our ability. In such cases, we do what is possible, but there are other considerations also.

Shrimati Jyotsna Chanda: Do Government propose to stop the supply of raw materials to Pakistan to run their factory in Sylhet, and do they intend to open a cement factory in the Khasi and Jaintia Hills in Assam?

Shri T. N. Singh: At present, there are no supplies being made to Pakistan. As regards the future, it is yet to be seen.

Shri Kajrolkar: Do Government intend to make cement available to the Maharashtra Government in response to their urgent need for it for implementation of big Industrial schemes and housing projects?

Mr. Speaker: That must be taken note of as he seldom puts a question.

Dr. P. Srinivasan: As we know, there is acute shortage of cement all over, but even the little quantity of cement available in the black market is found adulterated. What steps do Government propose to take to remedy that state of affairs?

Shri T. N. Singh: There is nothing unusual if black-marketeers and adulterators join together.

Shri Indrajit Gupta: The statement commences with the sentence that 'there is an overall shortage of cement in the country'. In view of this, what are the reasons which have impelled Government to decide on decontrol of cement, and how do they propose after decontrol to prevent the prices from going up without any kind of restriction?

Shri T. N. Singh: As the hon. Member is aware, due to the emergency, that decision has been postponed for the time being. The decision to decontrol was taken by the Prime Minister and the Government as it was felt that with the regulated system of supply of essential things that we are thinking of, it would be possible to do away with some of the evils that are there and at the same time, ensure better supply.

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, इस समय सारे देश में सीमेंट की तीन कीमतें हैं: एक, कंट्रोल की कीमत; दूसरी, कंट्रोल से नीचे की कीमत; और तीसरी, कंट्रोल से ऊपर की कीमत। सरकारी इमारतों के लिये सीमेंट कंट्रोल भाव से नीचे मिलता है। देहाती लोगों को कंट्रोल भाव से बहुत ज्यादा—बीस रुपये कट्टा—पर सीमेंट मिल रहा है। कुछ लोगों को कंट्रोल भाव पर भी सीमेंट मिल जाता है। इन तीन कीमतों का कारण है सरकार की दूषित वितरण-नीति। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नीति को जिस के अन्तर्गत बी० डी० ओ० और इस्पेक्टरों के द्वारा सीमेंट का बंटवारा होता है, समाप्त करने का विचार रखती है या नहीं ?

Mr. Speaker: Is the distribution policy to be revised or not?

Shri T. N. Singh: The whole policy was under consideration, and we were going to take certain steps . . .

श्री रामसेवक यादव : देशी भाषा में सवाल किया गया है और देशी भाषा में ही जवाब दीजिये।

श्री रामेश्वरानन्द : आप को तो हिन्दी आती है।

अध्यक्ष महोदय : आपने भी तो कान में लगा रखा है।

श्री त्रि० ना० सिंह : जैसा सदन को मालूम है कि इसके पहले अभी प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि सीमेंट का डिकंट्रोल होने वाला है। आज जो स्थिति है उसको देखते हुए उसको अभी नहीं किया गया है। लेकिन आगे क्या करना चाहिये, ये सब बातें अभी विचाराधीन हैं।

Some hon Members *rose*—

Mr. Speaker: The demand is so great and the supply is so little that I cannot satisfy all the members.

Shri Ranga: Are we to understand that the emergency is over, the Government are not going to give any thought to it at all, and there is a process of attrition by which the Prime Minister's wishes and Prime Minister's decisions, arrived at after having consulted the concerned Ministry, are being destroyed piecemeal by all sorts of excuses by the Minister concerned?

Shri T. N. Singh: The insinuation that the Prime Minister's decision is in any way being circumvented is quite wrong. We are going to honour whatever the Prime Minister has decided. The decisions were taken after full consideration by the Government. Let it however be admitted that the emergency is not over yet.

Shri Ranga: It has come for your benefit.

दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी

\+

*815. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में देश में बनी मशीनों तथा पुर्जों की स्थायी प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). There is a proposal under consideration of the Government to organize a Permanent Exhibition in New Delhi for the display of Indian manufactured products and with a view to present a picture of developing and changing India with particular reference to our development plans and export potential. It is also proposed to set up Showrooms for the display of India's exportable products particularly more manufactured products at the principal commercial and industrial centres of India such as Bombay, Calcutta, Madras, Delhi and Bangalore and some progress has already been achieved in this regard.

श्री म० ला० द्विवेदी : विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति न होने का एक कारण यह भी है कि उन उद्योगों में जो मशीनरी की आवश्यकता होती है उसका कहीं पर डिमण्ले नहीं होता है और जो पूरक उद्योग होते हैं, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है आपको बनाने की, उनका भी कहीं प्रदर्शन नहीं होता है, लिहाजा लोग उन्हें नहीं बना पाते है । मैं जानना चाहता हूं कि पूरक उद्योगों की आवश्यकताओं की और मशीनरी के प्रदर्शन की उचित व्यवस्था कब तक हो जाएगी ?

श्री मनुभाई शाह : जैसे सदन को पता है कि बहुत सी एग्जीबीशंज हिन्दुस्तान के अलग अलग शहरों में मुकामी व्यवस्था पर और हंगामी व्यवस्था पर हो रही है । यह जो सवाल था यह तो एक्सपोर्ट ओरियेंटेशन के लिए था ताकि जो फारेनर खरीददार हैं उनको यहां का सामान देखने के लिए कैसे मिले । इसके लिए एक परमानेंट एग्जीबीशन हम दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं जो कायम रहेगी । पांच छः बड़े बड़े शहरों के अन्दर भी स्पेशल एक्सपोर्ट ओरियेंटेशन को देखते हुए प्रोडक्ट्स को दिखाया जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि देशों में मेंउद्योगों . . .